Percentage distribution of casual wage employment (UPS) for male and female in rural and urban areas are as below:

	Rural			Urban			Total		
	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total
1993-94 (50th Round)	34.6	45.3	37.7	16.2	28.1	18.2	30.1	42.9	33.5
1987-88 (48th Round)	32.1	40.2	34.7	14.6	26.7	16.8	28.2	38.6	31.2

UPS : Usual Principal Status

The number of women in the Live Registers of Employment Exchanges at the end of 1988 stood at 5.5 million. The corresponding figure at the end of 1996 was around 8.4 million.

Recognising the high incidence of under employment and increasing casualisation of labour, there is need to enhance employment opportunities for poor with specific reference to female. In this context, the Ninth Plan will implement a National Employment Assurance Scheme. Special Employment Programmes, currently under operation, also provide employment to women.

Greater productive employment will be generated in the growth process itself by concentrating on Sectors, Sub-sectors and technologies which is labour intensive in regions characterised by higher rates of unemployment and under-employment. Improvements in the quality of employment can be achieved only in a situation of rapidly growing productivity to which the labour can lay a just claim.

गुजरात के अत्यंत पिछड़े जिलों में नवयुवकों के लिए रोजगार के अवसर

3918. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ल:** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कच्छ, पंचमहल, बनासकांठा, साबरकण्ठा, मेहसाना, सुरेन्द्र नगर और डांग गुजरात राज्य और देश के अत्यंत पिछड़े जिले हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन जिलों के शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने का विचार रखती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या चालू वित्तीय वर्ष और चालू पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए कोई प्रावधान किया गया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार भगतराम अलघ): (क) से (घ) किसी क्षेत्र की योजना एवं विकास और इस प्रयोजनार्थ निधियों का आबंटन मुख्यत: संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। योजना आयोग ने इसके अनुसार पिछड़े क्षेत्र के रूप में किसी क्षेत्र का पता नहीं लगाया है। परन्तु राज्यों में सामान्य केन्द्रीय सहायता देने के लिए प्रयुक्त फार्मूले, जनजातीय उपयोजना, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरूभूमि विकास कार्यक्रम और दूसरे कार्यक्रम/स्कीमों जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना और रोजगार अश्वासन स्कीमों जैसे विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत संसाधनों के हस्तांतरण की कार्य प्रणाली के माध्यम से गुजरात राज्य सहित केन्द्र सरकार इस संबंध में राज्य सरकारों के प्रयत्नों की मदद कर रही है।

पर्याप्त उत्पादक रोजगार उत्पन्न करने और गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से नौवीं योजना के दृष्टिकोण में कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना निहित है। बेरोजगारी की अधिक दरों और अल्परोजगार वाले क्षेत्रों में अधिक श्रमिकों की खपत वाले क्षेत्रकों, उपक्षेत्रकों और प्रौद्योगिकीयों में ध्यान केन्द्रित करके अधिक उत्पादक रोजगार उत्पन्न किए जाएंगे पारंपरिक व्यवसायों में लगे लोगों के लिए कार्यकौशल विकसित करने, प्रौद्योगिकी स्तरों को बढ़ाने और विपणन सुविधाएं प्रदान करने के लिए विशेष कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाएंगे।